भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय परिषद बैठक
स्व. सूर्यभान वहाडने पाटिल परिसर
7–8 फरवरी, 2009
नागपुर

राजनीतिक प्रस्ताव

केन्द्र में संप्रग सरकार का शासन समाप्त होने वाला है, शीघ्र ही लोकसभा के लिए आम–चुनाव होंगे। संप्रग सरकार की एकमात्र उपलब्धि यह है कि आज राष्ट्र प्रायः सभी मोर्चों पर संकट का सामना कर रहा है। इसका सीधा कारण केन्द्र सरकार की वह पद्धति है, जिसको लेकर वह देश का शासन चला रही है। डा0 मनमोहन सिंह की सरकार ने दृढ़ – निश्चयी नेतृत्व, निर्णायक शासन प्रणाली और सुसंगत नीति का कभी भी परिचय नहीं दिया।

भारत बना एक नरम राष्ट्र

संप्रग सरकार के कमजोर रवैये के कारण भारत एक बहुत ही नरम राष्ट्र के रूप में उभरा है। विगत साढ़े चार वर्षों से भी अधिक समय के दौरान भारत एक नरम देश और आतंक का चारागाह बन गया है। आतंकवादी जब चाहें जहां चाहें बिना खौफ हमला कर देते हैं। वे अन्य स्थानों के साथ–साथ भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली, वाणिज्यिक राजधानी मुम्बई, भारत की वैज्ञानिक राजधानी बंगलुरू और भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी पर भी हमला कर चुके हैं। चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो या पश्चिम हो देश का कोई भी भाग आतंकवादियों के घातक हमलों से सुरक्षित नहीं है।

26 नवम्बर को मुम्बई पर हुआ आतंकी हमला इस क्रम में हुए हमलों में सबसे भयावह था। यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा सुनियोजित रूप में और सैनिक कुशलता के साथ निष्पादित किया गया था, जिसको आई.एस.आई. सहित पाकिस्तानी संस्थान के प्रमुख अंग के निर्देशन में आधुनिकतम प्रशिक्षण देकर कराया गया था। वस्तुतः, यह हमला भारत पर हुआ था जिसमें हमारी कमजोरियां खुलकर उजागर हुई थीं। आतंकवादियों ने कराची से समुद्री मार्ग अपनाया वे मुम्बई के किनारे पहुंचे उन्होंने जानेमाने होटलों पर हमला किया जो देश के ऐतिहासिक धरोहर हैं। इसके साथ–साथ आतंकवादियों ने बेखौफ सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन पर हमला करके सैकड़ों लोगों को निर्भकतापूर्वक मार डाला। फिर भी देश का सम्पूर्ण खुफिया तंत्र पूरी तरह पंगु सा प्रतीत हुआ, जिसके पास हमले को रोकने के लिए ना कोई विश्वसनीय सूचना थी और न ही कोई सार्थक कार्रवाई की योजना थी। देश ने वास्तविक अर्थों में सिविल वार और विभिन्न सूचना एजेंसियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप लगाने का खेल देखा। यह स्वतः स्पष्ट है कि निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व द्वारा बेहतर समन्वय तथा सामयिक पहल करके इस हमले और अनेक निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या को रोका जा सकता था।

पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने स्तब्धकारी रूप में दिखा दिया कि भारत जेहादी आतंकवादियों के ग्रुप के सामने कितना कमजोर और निरीह है। पाकिस्तान अपने चरित्र के अनुरूप हर बात से बार–बार इंकार कर रहा है, यहां तक कि उसने आतंकवादियों के पाकिस्तानी मूल के होने से भी इंकार कर दिया है। यह समय न केवल कठोर उपायों का है, बल्कि कठोर कार्रवाई करने का भी है। सरकार जो भी उपाय करना चाहेगी भाजपा उनका समर्थन करेगी, किन्तु किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान–स्थित आतंकवादियों, उनके संचालकों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि उन सभी को जो इस हमले के जिम्मेदार हैं तथा जिन्होंने इसका षडयंत्र रचा था और दुष्प्रेरित किया था, भारत को ट्रायल हेतु उसे सौंपना चाहिए। सरकार को इस बारे में कोई भी कठोर कार्रवाई करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि पाकिस्तान ने सही जवाब देने की इच्छा नहीं दिखाई तब क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। वरिष्ठ मंत्री बार–बार दोहरा रहे हैं कि सारे विकल्प खुले हैं तथा समय–समय पर वे एक–दूसरे की बातों का खंडन करते भी देखे जाते हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कई बार मंत्रियों की टिप्पणियों का खंडन करते हैं। सारे राजनयिक प्रयास भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गए हैं। भाजपा मांग करती है कि यदि पाकिस्तान मुम्बई तथा अन्य स्थानों पर हुए आतंकी हमलों में लिप्त सभी आतंकवादियों को जिनमें, दाऊद इब्राहीम भी शामिल है को भारत को सौंपने सहित अन्य उचित कार्रवाई नहीं करता है तो सरकार को पाकिस्तान के साथ व्यापार, परिवहन, पर्यटन तथा सांस्कृतिक–सभी तरह के संबंध समाप्त करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मगर इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार की नीतियों ने भारत को बार–बार होने वाले आतंकी हमलों से कमजोर बना दिया है। आतंकवादियों को, देश के अंदर रहने वाले उनके संरक्षकों तथा सीमापार बसे उनके आकाओं को बार–बार संकेत दिए गए हैं कि वोट के लिए उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई का सौदा किया जा सकता है। सत्ता में आने के बाद संप्रग ने एक ऐसी कार्य–संस्कृति को पनपने की अनुमति दे दी है। जिसमें आतंकवाद की प्रत्येक धमकी को कम से कम कर बताने का प्रयास किया जाता है। बार–बार आतंक को इसलिए कम करके आंका जाता है कि कहीं राजग अपने दलगत एजेंडा के लिए इसको बढ़ा–चढ़ा कर पेश न कर दें। पोटा कानून के निरस्ति का धर्म निरपेक्षता की जीत के रूप में स्वागत किया गया था हालांकि उच्चतम न्यायालय ने पोटा को सांविधानिक रूप से वैध घोषित किया था। आतंकवादियों को गुमराह युवक बताया गया था। ऐसे परिवेश में सुरक्षा एजेंसियों में साहस और विश्वास के साथ आतंक से लड़ने का उत्साह समाप्त हो गया था कि कहीं इससे सांप्रदायिकता की छाप न लग जाए। संप्रग सरकार सुरक्षा एजेंसियों के बार–बार दिए गए सुझाव के बावजूद कठोर आतंक–विरोधी कानून की आवश्यकता को पूरे चार वर्ष तक अस्वीकृत करती रही। अंततः, मुम्बई पर हुए हमले के बाद विधि–विरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 में कुछ संशोधन किए गए। यद्यपि भाजपा ने उनका समर्थन किया तथापि कठोर सचाई यह है कि इसमें अभी भी अनेक खामियां है जो आतंक के विरूद्ध लड़ाई में सुरक्षा तथा अन्वेषण एजेंसियों के लिए समस्याएं पैदा करती रहेगीं।

एक महान् विभूति बनने की चाह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ अपने व्यवहार में कुछेक बुनियादी तथा प्राथमिक तथ्यों को तिलांजलि दे दीं। उनके द्वारा पाकिस्तान को आतंकवाद–पीड़ित देश बताया जाना और उसके साथ संयुक्त आतंक–विरोधी तंत्र को प्रस्तावित किया जाना एक बृहद् राजनयिक भूल थी। भारत को सैकड़ों प्रकार की क्षति पहुंचानें तथा दुर्बल बनाने के लिए पाकिस्तान ने आतंक को एक सुनियोजित नीति–उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान को इस रणनीति से भारी लाभ पहुंचा है। यदि इसमें से कुछ आज पाकिस्तान पर उल्टे भारी पड़ रहे हैं तो भी पाकिस्तान को पीड़ित देश नहीं कहा जा सकता क्योंकि आई.एस.आई. और सुरक्षा बलों के संस्थान के प्रमुख अंग अभी भी इसी नीति का भरपूर अनुसरण करते हैं। मुम्बई पर हमला इसी षडयंत्र का हिस्सा था। संप्रग सरकार के शासन में देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को हल्का कर दिया गया है। हाल ही में इंग्लैड के विदेश मंत्री श्री डेविड मिलीबैण्ड ने भारत आकर अत्यंत ही आक्रामक रूप से कहा कि आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा एक दूसरे से जुड़े है। इस वक्तव्य का भाजपा ने विरोध किया लेकिन भारत सरकार ने अभी तक ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध सही ढंग से विरोध प्रकट नहीं किया है।

वोट बैंक राजनीति

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वोट बैंक राजनीति के प्रति संप्रग की प्रतिबद्धता आतंक के विरूद्ध लड़ाई में गंभीर बाधा पैदा कर रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण नई दिल्ली में जामिया मिलिया स्थित बाटला हाउस में हुई मुठभेड़ है। जहां सरकार उस पुलिस अधिकारी को जो आतंकवाद से युद्ध करते हुए शहीद हो गया था, अशोक–चक्र से पुरस्कृत करती है; वहीं सरकार के वरिष्ठ मंत्री बार–बार उस घटना की जांच कराए जाने की मांग करते रहते हैं। सरकार उच्चतम स्तर से भी इसके लिए स्पष्ट रूप से इंकार नहीं करती है। अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ प्रमुख धार्मिक नेताओं द्वारा बार–बार की गई इस घोषणा, कि आतंकवाद अमानवीय है, से भी वोट बैंक राजनीति हेतु होड़ में कोई कमी नहीं आई हैं। दक्षिण में रामसेतु का मुद्दा, जिसके दौरान भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताया गया था, उत्तर में जम्मू–कश्मीर में श्री अमरनाथ की तीर्थयात्रा हेतु भूमि की वापसी, वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा सिमी को सांस्कृतिक संगठन बताया जाना; धर्म के आधार पर आरक्षण जिसकी दृष्टि से अनुमति संवैधानिक नहीं दी जा सकती, इन सब में हमनें राष्ट्रीय अखंडता की महती लागत पर वोट बैंक राजनीति की घिनौनी सक्रियता देखी है। यह स्वाभाविक ही है कि वोट बैंक राजनीति की इन कारगुजारियों से ही देश के अंदर और बाहर आतंकवादियों और उनके आकाओं ने भारत को क्षति पहुंचाने तथा अपमानित करने की हिम्मत जुटाई है। नेतृत्व की विफलता और समय पर कार्रवाई करने के प्रति कोताही ने एक सुरक्षित भारत की दुर्भाग्यपूर्ण वसीयत छोड़ी है।

आज पूर्वोत्तर भारत में अतिवाद तथा बांग्लादेश से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ ने बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। संप्रग सरकार कश्मीर में पाकिस्तान प्रशिक्षित मिलिटेंटों, बांग्लादेश से आई.एस.आई. समर्थित हूजी के कार्यकर्ताओं और नेपाल से माओवादी गुरिल्लाओं की घुसपैठ पर अंकुश लगाने में बुरी तरह विफल रही है। इस्लामिक जेहादियों, अनेक प्रकार के अलगाववादियों और अतिवामपंथी आततायियों के जमघट का सामना होने पर संप्रग सरकार ने इस चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने की बजाय भारत के लोगों को अपने भाग्य के सहारे छोड़ दिया है। कई राज्यों में नक्सलवाद एक गंभीर खतरा बन गया है छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो नक्सली हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित है। भाजपा राज्य के लोगों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव का

बहिष्कार करने की नक्सलवादियों की खुली धमकी का बहादुरी से सामना किया; भारी संख्या में मतदान किया तथा नक्सली हिंसा द्वारा प्रभावित लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवारों को अभूतपूर्व सफलता दिलाई। राज्य सरकार ने उन निर्दोष वनवासियों को सुरक्षा देने के लिए सलवा–जूडूम कैम्प लगाए हैं, जो अपने गांव में नक्सलवादियों के हाथों मौत की धमकी का सामना करते हैं। इन कैम्पों के विरूद्ध एक विषैला और स्वार्थपूर्ण अभियान चलाया गया, जिसको चलाए जाने में राज्य की कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हैं। संप्रग सरकार ने ऐसे अभियान के विरूद्ध कोई स्पष्ट रूख नहीं अपनाया। जो लोग मानवाधिकारों की बात करते हैं उनसे यह एक सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है कि क्या आतंकवादी तथा नक्सली हिंसा के पीड़ित व्यक्तियों के कोई मानवाधिकार हैं या नहीं हैं अथवा यह विलासिता केवल उन्हीं लोगों को सुलभ हैं जो बेखौफ हमला करते हैं और कत्ल करते हैं?

नए गृहमंत्री को बांग्लादेश से घुसपैठ के खतरे का अब कुछ–कुछ आभास हो चला है। अब काफी देर हो चुकी है। यह उन्हीं की अपनी सरकार थी जिसने इस खतरे की बार–बार अनदेखी की तथा उच्चतम न्यायालय के उन निर्देशों की अवहेलना की जहां पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हो रहे आप्रवासन को बाहरी आक्रमण तथा आतंरिक उपद्रव के समान ठहराया था और सरकार को चेताया था कि वह इसके विरूद्ध संविधान सम्मत सभी तरह की कार्रवाई करें बांग्लादेशियों के आतंकी हमलों में लिप्त होने की बार–बार की सूचनाओं के बावजूद वोट–बैंक की राजनीति के चलते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि बांगलादेशी घुसपैठियों को तुरंत पहचानकर उनको निश्चित समय सीमा के अंदर उनकी वापसी सुनिश्चित करें। भाजपा यह भी मांग करती है कि जिस तरह से भारत की पश्चिमी सीमा पर कांटेदार बाढ़ लगायी गई उसी तरह भारत की पूर्वी सीमा पर भी कांटेदार बाढ़ लगाने के लिए समय–सीमा तय की जाये।

आज देश भाजपा की तरफ देख रहा है कि वह आतंकवादियों, अतिवादियों, सिमी जैसे तथा अन्य प्रकार के इस्लामिक जेहादियों, नक्सलवादियों तथा अन्य अलगाववादी तत्वों द्वारा बार–बार के तथा विषैले आक्रमणों से देश की रक्षा करें। श्री लालकृष्ण आडवाणी के प्रभावी नेतृत्व में भाजपा सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने के लिए कृत–संकल्प है।

भारतीय जनता पार्टी श्रीलंका समस्या के शीघ्र समाधान की मांग करती है। भारत लिट्टे और श्रीलंका सेना के बीच फंसे निर्दोष तमिलों और श्रीलंका के बीच विविध विपक्षीय संधियों का पालन करते हुए श्रीलंका में बसे हुए लाखों तमिल लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में सरकार आवश्यक पहल करें। इस समस्या के समाधान के लिए एक शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक प्रस्ताव का भाजपा समर्थन करती है।

असंगत गठबंधन

भारत इसीलिए पीड़ाग्रस्त है क्योंकि उसपर एक असंगत गठबंधन का शासन है, जिसमें भाजपा का विरोध करने की ऐसी मजबूरी है जो सबको बांधे रखती है वामपंथियों ने इस गठबंधन को बीच मार्ग में छोड़ दिया है तथा कांग्रेस ने खुलेतौर पर घोषित किया है कि उसका किसी राजनीतिक दल के साथ कोई राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है। ऐसे भी, कांग्रेस को गठबंधन चलाना कभी रास नहीं आया। एक अवसरवादी गठबंधन सुशासन और विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता। यदि नेतृत्व दुर्बल है तो यह अच्छा प्रदर्शन किए बिना सत्ता से जुड़े रहने मात्र के लिए विवश हो जाता है। हताशा जनित ऐसे गठबंधन के पास अपने ट्रैक रिकार्ड के कारण वैधता प्राप्त करने के लिए कोई नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब संप्रग के घटकों के नेताओं के बीच स्वयं प्रधानमंत्री बनने की भारी होड़ मची हुई है। देश को यह जानने का हक है कि संप्रग का भावी प्रधानमंत्री कौन है? इसके अतिरिक्त संप्रग के विभिन्न घ टकों तथा समर्थकों के बीच परस्पर युद्ध छिड़ा हुआ है। डी.एम.के बनाम पी.एम.के, एस.पी. बनाम कांग्रेस, लालू प्रसाद बनाम राम विलास पासवान, (आर.जे.डी बनाम एल.जे.पी)। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस से आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा पाल रखी है। ये कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत हैं जो एक अस्थिर और अयोग्य गठबंधन के परिचायक है।

वामदल पुनः तीसरे मोर्चे का भ्रम इस बात का एहसास किए बिना पाल रहे हैं कि इसकी समय और प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है। ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि समाजवादी पार्टी तथा राजद पुनः कांग्रेस के निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं। देश को यह जानने का हक है कि उनकी हैसियत क्या है–अधिकृत प्रतिपक्ष या कांग्रेस का समर्थक। इस तरह की जोड़–तोड़ और राजनीतिक अवसरवादिता से देश के लोग क्षुब्ध हो उठे हैं।

संस्थाओं का ह्रास

संप्रग द्वारा संस्थागत विश्वसनीयता के दुरूपयोग से भारी ह्रास हुआ है। मनमोहन सिंह सरकार की बहुमत की परीक्षा के दौरान लोकसभा के पटल पर वोट के बदले कैश ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में राजनीतिक भ्रष्टाचार की नई गिरावट का परिचय कराया था। उन प्रमुख दोषियों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, जिन्होंने संसदीय प्रक्रिया और संस्थागत निष्ठा के इस स्तब्धकारी पतन को प्रायोजित तथा आयोजित किया। इस घ

ाोटाले की तहकीकात के लिए गठित संसदीय समिति की प्रतिष्ठा भी शक के घेरे में आ गई है। अब जिन लोगों ने इस घोटाले पर से पर्दा हटाया था उन्हीं पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सरकार ने सी.बी.आई. का भरपूर दुरूपयोग किया है। सी.बी.आई. उस राजनीतिक नेता के विरूद्ध जोर–शोर से अभियोजन चलाती है, जो संप्रग सरकार के विरूद्ध है तथा जैसे ही वह नेता सरकार का समर्थक बन जाता है वैसे ही सी.बी.आई. अपनी करनी से पूरी तरह पलट जाती है। यह तथ्य कुमारी मायावती तथा श्री मुलायम सिंह यादव की आय से अधिक संपत्तियों के बारे में चल रही कार्रवाइयों से स्पष्ट हो जाता है। सी.बी.आई. कुख्यात चारा घोटाले में प्रमुख अभियोजक थी जिसमें रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव मुख्य अभियुक्त थे। जब श्री लालू प्रसाद यादव को आय से अधिक अनुपात में संपत्ति संबंधी अभियोजन के बारे में एक संदिग्ध फैसले में बरी किया गया था तब सी.बी.आई. ने इस फैसले को चुनौती देने के बजाय उक्त फैसले के विरूद्ध अपील किए जाने का विरोध करने के प्रयास किए थे। सी.बी.आई. के दुरूपयोग के इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। एक चुनाव आयुक्त के पक्षपातपूर्ण आचरण से संबंधित हाल के मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया भी सरकार की संस्थागत निष्ठा के प्रति अभाव पर पुनः प्रकाश डालती है फिर चाहे इसमें हमारे लोकतंत्र के प्रति महत्व रखने वाले निर्वाचन आयोग जैसी शीर्ष संस्था ही क्यों न संलिप्त हो। यूपीए सरकार के दबाव में अनेक राज्यपालों ने राजनैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। गोवा और झारखंड में इस घोर उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। झारखंड की वर्तमान स्थितियों में सरकार बनने की कोई संभावना न होने के कारण वहां तत्काल चुनाव कराये जाने चाहिए।

विकास को पटरी से उतारा

जैसे–जैसे संप्रग के सत्ता से जाने का समय आ रहा है वैसे–वैसे विकास की गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर जाने के साक्ष्य बढ़कर सामने आ रहे हैं। जिस आम आदमी के हित को संरक्षित करने का संप्रग ने मिथ्या दावा किया था वही संप्रग के शासन में सर्वाधिक पीड़ा का शिकार है। गत दो वर्षों के दौरान लगातार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने न ही किसी विजन का परिचय दिया और न ही कोई दीर्घकालिक योजना बनाई। अब मुद्रास्फीति की दर नीचे आने के दावों के बावजूद जमीन पर वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों में कहीं कमी की झलक नहीं मिल रही हैं। आम आदमी के लिए जीवन निर्वाह करना दुष्कर होता जा रहा है। अब वैश्विक मंदी भारत को कड़ी चोट पहुंचाने जा रही है। भारी संख्या में बेरोजगारी का संकट क्षितिज पर उभर रहा है। एक अनिर्णायक संप्रग सरकार जिसने शुरू में इस समस्या के वजूद से ही इंकार कर दिया था, ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। भारतीय उद्योग ने भारतीय निर्यात में 12 प्रतिशत की कमी हो जाने के कारण गत वर्ष अक्तूबर में 0.4 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की थी। निर्माण क्षेत्र में भी एक वर्ष पहले के 13 प्रतिशत से घटकर गत वर्ष अक्तूबर में 1.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की। कृषि क्षेत्र भी सुखद स्थिति में नहीं है। किसानों की आत्महत्याएं अब भी जारी हैं। हमारे नागपुर में इकट्ठा होने के समय पर भी विदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के बावजूद किसानों की सर्वाधिक संख्या में आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं।

ऋणात्मक वृद्धि का सबसे बड़ा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्र है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चिरकालिक विलंबों, तदर्थवाद तथा निगरानी के अभाव का शिकार है, जिसमें निर्णय करने में बाहरी तत्वों की भूमिका रहती है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी नीत पूर्व की राजग सरकार के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम फेज–I में वृद्धि 81 प्रतिशत थी। अब इसके विपरीत इस कार्यक्रम में संप्रग सरकार के घिसे–पिटे निकम्मेपन के कारण यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सभी मोर्चों पर विफलता का शिकार हो गई है। आजकल इस कार्यक्रम के सभी चरणों में निकम्मेपन का आलम है। आधारभूत संरचना के अन्य क्षेत्र भी अफसोसनाक दृश्य उपस्थित करते है। संचार विभाग में स्पेक्ट्रम घोटाले का घुन लग गया है जबकि वाणिज्य मंत्रालय में विशेष आर्थिक ज़ोन के नाम पर भूमि के व्यापार में घपलें हो रहे हैं।

देश भाजपा की ओर देख रहा है

कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार एक उत्पीड़ित और असुरक्षित भारत को विरासत में छोड़ रही है। यह स्वाभाविक ही है कि देश अब भाजपा की ओर निहार रहा है और भाजपा नीत राजग द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का स्मरण कर रहा है जिनके कारण भारतीयों के चेहरों पर हर्ष और मुस्कान बिखर गई थी। भाजपा सभी भारतीयों से अपील करती है कि वे देश को संप्रग सरकार के कुशासन से मुक्त कराएं और भारत की सुरक्षा विकास तथा समृद्धि के लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व के अधीन भाजपा–नीत राजग सरकार की वापसी सुनिश्चित करें।

****